CIVIL SERVICES (MAIN) EXAM-2022

वियोज्य *DETACHABLE*

लोक प्रशासन (प्रश्न-पत्र II)

PUBLIC ADMINISTRATION (Paper II)

निर्धारित समय : तीन घण्टे
Time Allowed : Three Hours

CIVIL SERVICES (MAIN) EXAM-2022

अधिकतम अंक : 250
Maximum Marks : 250

प्रश्न-पत्र सम्बन्धी विशेष अनुदेश

उत्तर देने के पूर्व निम्नलिखित निर्देशों को कृपया सावधानीपूर्वक पढ़ें :

इसमें **आठ** प्रश्न हैं जो **दो खण्डों** में विभाजित हैं तथा **हिन्दी** एवं **अंग्रेजी** दोनों में छपे हुए हैं ।

परीक्षार्थी को कुल **पांच** प्रश्नों के उत्तर देने हैं ।

प्रश्न संख्या **1** और **5** अनिवार्य हैं तथा बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खण्ड से कम-से-कम **एक** प्रश्न चुनकर **तीन** प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं ।

प्रश्नों के उत्तर उसी प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए, जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुखपृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए । प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे ।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए ।

प्रश्नों के उत्तरों की गणना क्रमानुसार की जाएगी । यदि काटा नहीं हो, तो प्रश्न के उत्तर की गणना की जाएगी चाहे वह उत्तर अंशतः दिया गया हो । प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए ।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions :

There are **EIGHT** questions divided in **TWO SECTIONS** and printed both in **HINDI** and in **ENGLISH**.

Candidate has to attempt **FIVE** questions in all.

Question Nos. **1** and **5** are compulsory and out of the remaining, **THREE** are to be attempted choosing at least **ONE** from each Section.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Attempts of questions shall be counted in sequential order. Unless struck off, attempt of a question shall be counted even if attempted partly. Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

खण्ड 'A' SECTION 'A'

1. निम्नलिखित में से प्रत्येक का लगभग 150 शब्दों में उत्तर दीजिए।
Answer the following in about 150 words. 10×5=50

1.(a) "मुगल प्रशासनिक व्यवस्था केन्द्रीयकृत निरंकुशतावादी थी।" टिप्पणी कीजिये।
"Mughal administrative system was centralised despotism". Comment. 10

1.(b) "उपनिवेशवाद से लेकर वर्तमान तक बदलते हुए समय के बावजूद जिला कलैक्टर का पद सराहनीय रूप से अब भी टिका हुआ है।" टिप्पणी कीजिए।
"The office of the District Collector admirably survived the changing times from colonialism to the present times". Comment. 10

1.(c) "मंत्रालयों एवम् विभागों में कार्यों का निर्बाध संपादन मन्त्रिमण्डलीय सचिवालय की भूमिका पर निर्भर करता है।" विवेचना कीजिये।
"The smooth transaction of business in Ministries and Departments depends on the role played by Cabinet Secretariat". Discuss. 10

1.(d) "भारत सरकार अधिनियम, 1935 भारतीय संविधान का सबसे महत्त्वपूर्ण स्रोत है।" इसकी विशेषताओं की पहचान कीजिए।
"The Government of India Act, 1935 is the most important source of Indian constitution". Identify its features. 10

1.(e) "मुख्य सचिव राज्य और केन्द्र सरकार के बीच मुख्य संचार-कड़ी है"। व्याख्या कीजिए।
"The Chief Secretary is the chief communication link between the state and central government". Explain. 10

2.(a) "भारतीय संघ का ढाँचा, कुछ असममित (असिमैटरिक) विशेषताओं के बावजूद, काफी हद तक सममित (सिमैटरिक) है।" भारत में भारित और विभेदित समानता के सिद्धान्त के माध्यम से राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों की स्थिति का परीक्षण कीजिए।
"The Indian federal structure is largely symmetric albeit with some asymmetric features". Examine the status of States and Union Territories through the principle of weighted and differentiated equality in India. 20

2.(b) आत्मनिर्भर भारत अभियान एक प्रगतिशील नीति है। विश्लेषण कीजिए।
The Atmanirbhar Bharat Abhiyaan is a progressive policy. Analyse. 20

2.(c) 'सांकेतिक नियोजन सार्वजनिक एवम् निजी गतिविधियों के बीच समन्वय को आश्वस्त करने हेतु नियोजन एवम् बाजारतंत्र का एक मध्य पथ है।' व्याख्या कीजिये।
'Indicative Planning, is a middle path of planning and market mechanism to ensure coordination between public and private activities.' Explain. 10

3.(a) "विगत तीन दशकों के दौरान हुए नवीन आर्थिक सुधारों ने न केवल औद्योगिक लाइसेंस (अनुज्ञापत्र) के क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के लिये अनन्य आरक्षित क्षेत्र को घटाया है बल्कि विद्यमान सार्वजनिक उपक्रमों की स्वायत्तता को भी अतिक्रमित किया है।" परीक्षण कीजिये।
"The New Economic Reforms during the past three decades have not only reduced the scope of industrial licensing and areas reserved exclusively for Public Sector but also infringed the autonomy of existing public sector undertakings". Examine. 20

3.(b) "राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति) आयोग हमारे देश की विकास कार्यसूची तैयार करने में 'सुपर केबीनेट' बन चुका है।" उपयुक्त उदाहरणों सहित इस कथन का परीक्षण कीजिये।
"National Institution for Transforming India (NITI) Ayog has become super cabinet in formulating the development agenda of our country". Examine the statement by giving suitable examples. 20

3.(c) संवैधानिक स्थिति के बावजूद जिला नियोजन समितियाँ योजनाओं को तैयार करने और उन्हे क्रियान्वित करने में अस्तित्वहीन बनी रही हैं। विवेचन कीजिए।

Despite the constitutional status, the District planning committees remained a non-entity in preparation and implementation of plans. Discuss. 10

4.(a) ''भारतीय न्यायिक व्यवस्था शीघ्र न्याय प्रदान करने में असफल रही है''। न्यायपालिका के सम्मुख चुनौतियों का परीक्षण कीजिए तथा उन्हे दूर करने के उपाय भी सुझाएं।

"The Indian judicial system has failed to deliver justice expeditiously". Examine the challenges faced by the judiciary and suggest measures to overcome them. 20

4.(b) एक राष्ट्र – एक कर नीति के विशेष सन्दर्भ में संघ-राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित विवादों के विशिष्ट क्षेत्रों का विश्लेषण कीजिए।

Analyse the specific areas of controversies with regard to Union-State financial relations, particularly in the context of one nation – one tax policy. 20

4.(c) अंतर्राज्यीय नदियों के पानी से संबंधित विवादों के न्याय-निर्णय में केन्द्रीय सरकार की भूमिका का परीक्षण कीजिए।

Examine the role of central government in adjudication of disputes relating to water of interstate rivers. 10

खण्ड 'B' SECTION 'B'

5. निम्नलिखित में से प्रत्येक का लगभग 150 शब्दों में उत्तर दीजिए।

Answer the following in about 150 words. 10×5=50

5.(a) भारतीय संविधान के XIV वें भाग के सन्दर्भ में सरकार में पार्श्व प्रवेश भर्ती का परीक्षण कीजिए।

Examine the lateral entry recruitment in government in the context of Part XIV of the Indian Constitution. 10

5.(b) प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों को सुरक्षित करने में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की भूमिका का परीक्षण कीजिये।

Examine the role of Securities and Exchange Board of India (SEBI) in protecting the interests of the investors in securities. 10

5.(c) भारत में नागरिक अधिकारपत्र प्रशासनिक व्यवस्था को नागरिक केन्द्रित बनाने के उसके उद्देश्य में सफल नहीं हुए है। कारण दीजिये।

Citizens charters in India have not succeeded in their objectives in making administrative system citizen centric. Do you agree ? Give reasons. 10

5.(d) भूमण्डलीकरण के प्रारम्भ के अनुगमन में, पारम्परिक नौकरशाही प्रतिमान अपने महत्त्व को खोता प्रतीत होता है। टिप्पणी कीजिये।

Following the onset of globalisation, the traditional bureaucratic model appears to have lost its significance. Comment. 10

5.(e) ''नगरीय स्थानीय निकायों की वित्तीय उपयुक्तता तभी वास्तविक बन सकती है जब उन्हे सार्वजनिक वित्त में उचित हिस्सा प्राप्त हो।'' व्याख्या कीजिए।

"The financial suitability of the Urban local bodies can become a reality only when they receive their due share of public finances." Explain. 10

6. (a) राष्ट्रीय वित्त आयोगों की अनुशंसाऐं आवश्यकता आधारित होने के बजाय मानक आधारित होती है । इस कथन के प्रकाश में 15वें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों का विश्लेषण कीजिये ।

The recommendations of National Finance Commissions are more norms based than the need based. In the light of this statement analyse the terms of references of 15th National Finance Commission. 20

6. (b) ''मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य भारतीय सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण में वृद्धि करना और (अभि)शासन में सुधार करना है ।'' विवेचन कीजिए ।

"The objective of Mission Karmyogi is to enhance capacity building of Indian Civil Servants and improve governance." Discuss. 20

6. (c) प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण न्यायिक नियन्त्रण का प्रतिस्थानापन्न नहीं है । टिप्पणी कीजिये ।

Parliamentary control over administration is no substitute for judicial control. Comment. 10

7. (a) भारत में, बहुसंख्यक लोगों के उत्थान के लिए सरकारी हस्तक्षेप जीवन का एक केन्द्रीय तथ्य बना हुआ है । फिर भी, नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन लोकसेवकों के नैतिक मूल्यों पर निर्भर करता है । विवेचन कीजिए ।

In India, for the upliftment of majority of people, governmental intervention remains a central fact of life. Nevertheless, the effective implementation of policies depends on the ethical values of Public Servants. Discuss. 20

7. (b) आज सरकारी संस्थानों की निर्णय लेने और कार्य करने की व्यापक एवं अंगघाती अनिच्छा की मुख्य वजह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है । विवेचन कीजिए ।

Comptroller and Auditor General (CAG) is today a primary cause of widespread and paralysing unwillingness on the part of government institutions to decide and act. Discuss. 20

7. (c) क्या आप सोचते हैं कि नवीन स्थानीयवाद 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 की भावना को निर्वासित करता है ?

Do you think that the new localism relegate the spirit of 74th Constitutional Amendment Act, 1992 ? 10

8. (a) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समाज को अपनी आजीविका एवं पारम्परिक अधिकारों पर नियंत्रण करने में सक्षम बनाना है । इस अधिनियम के क्रियान्वयन का समालोचनात्मक रूप से परीक्षण कीजिए ।

The main objective of Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 is to enable tribal society to assume control over their livelihoods and traditional rights. Critically examine the implementation of the Act. 20

8. (b) कानून एवं व्यवस्था प्रशासन की प्रभावशीलता लोगों की पुलिस के प्रति सहयोगी अभिवृत्ति पर निर्भर करती है, न कि कानून व्यवस्था की संरचना और कार्यविधि तंत्र में सुधार करने पर । क्या आप सहमत हैं ? कारण दीजिये ।

The effectiveness of law and order administration depends on cooperative attitudes of people towards police, than bringing reforms in the structure and procedures of law and order machinery. Do you agree ? Give reasons. 20

8. (c) भारतीय प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेयता सुनिश्चित करने में लोकपाल की भूमिका का परीक्षण कीजिए ।

Examine the role of Lokpal in ensuring transparency and accountability in Indian administration. 10

Examrace